

# मूक पत्रिका

## निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02    अंक - 333    बेमेतरा, बुधवार 29 जुलाई 2026    रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित    कुल पेज - 08    मूल्य - 1 रुपये    डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

## विश्व मंच पर छत्तीसगढ़ की बेटी का दमदार प्रदर्शन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉल पर दी बधाई

**रायपुर।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाली राजनांदागांव निवासी एवं छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक ज्ञानेश्वरी यादव से वीडियो कॉल के माध्यम से आत्मीय बातचीत कर उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने पर पुनः बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता वर्षों की कठिन साधना और निरंतर परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी भविष्य में भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत और छत्तीसगढ़ का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आपसे प्रतियोगिता के लिए रवाना होने से पहले भी मुलाकात हुई थी और आज आपकी सफलता पर पुनः बात करके अत्यंत



प्रसन्नता हो रही है। आपने अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से न केवल छत्तीसगढ़

बल्कि पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आपकी उपलब्धि प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रदेश की प्रतिभाएं विश्व मंच पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। ज्ञानेश्वरी यादव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आत्मीय स्नेह, प्रोत्साहन और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद और प्रदर्शवासियों का स्नेह उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि राजनांदागांव निवासी ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के रूप में सेवाएं दे रही हैं। खेल और सेवा, दोनों क्षेत्रों में उनका समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणादायी है।

## ईओडब्ल्यू ने कांकेर में 18 साल पुराने मनरेगा अनियमितता मामले में आठ अधिकारियों के खिलाफ चालान किया पेश

**रायपुर।** कांकेर जिले में वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत, कांकेर में तत्कालीन जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित आठ अधिकारियों के खिलाफ लगभग छह हजार पन्नों का चालान प्रस्तुत किया है। ईओडब्ल्यू से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, जांच में आठ ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत सामग्री खरीद के दौरान एक करोड़ 69 लाख 14 हजार 247 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध अदालत में अभियोजन चालान पेश किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ केपी देवांगन ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना जिला स्तर पर सामग्री की केंद्रीकृत



खरीदी कराई, जबकि नियमों के अनुसार सामग्री खरीदने का अधिकार संबंधित जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को प्राप्त था। जांच में यह भी पाया गया कि फ्लेक्सी बोर्ड, मस्टर रोल सत्यापन पत्रक, रोजगार गारंटी योजना की गाइडलाइन, रोजगार उपलब्धता रजिस्टर, फाइल कवर, मस्टर रोल पत्रक तथा श्रमिक जानकारी पत्रक सहित विभिन्न सामग्रियों की खरीदी निर्धारित निविदा एवं शासकीय प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई। चालान में देवांगन के अलावा तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ राधाकांत

कर (कांकेर), गोवर्धन गजबल्ल (नरहरपुर), परदेशी राम मरकाम (चारामा), भारत राम नेताम (अंतागढ़), रामकिशुन ध्रुव (कोयलीबेड़ा), जीआर ठाकुर (भानुप्रतापपुर) तथा संवालदास बघेल (दुर्गाकौदल) को आरोपी बनाया गया है। ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार सभी आरोपियों ने कथित रूप से आपसी मिलीभगत से निविदा और शासकीय खरीद संबंधी नियमों की अनदेखी की तथा पद का दुरुपयोग कर सरकारी राशि के अनियमित उपयोग को अंजाम दिया। मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी), 13(1)(डी) और 13(2) के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी केपी देवांगन के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग से जुड़े दो अन्य मामले पहले से लंबित हैं।

## आरएसएस ने टी.जी. मोहनदास की टिप्पणियों की निंदा की संगठन को उनके विचारों से किया अलग

**कोच्चि।** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों, जिनमें सीजेपी का प्रदर्शन भी शामिल हैं, के संबंध में टी.जी. मोहनदास की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। संघ ने कहा है कि उनके बयान उनकी निजी राय थे और वे संगठन के विचार नहीं हैं। 'आरएसएस के दक्षिण केंद्रीय प्रांत सह-कार्यवाह के.बी. श्रीकुमार ने कहा कि संगठन का मोहनदास द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से कोई संबंध नहीं है और वह किसी भी तरह से ऐसी राय का समर्थन या उनसे सहमत नहीं रखता है।



आरएसएस में किसी भी स्तर पर कोई जिम्मेदारी या पद नहीं संभालते हैं। इस बीच, केरल सरकार ने नीट विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ मोहनदास के कथित नफ़रत भरे भाषण की पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह उनके कथित बयानों की जांच करे और सरकार को रिपोर्ट सौंपे। सरकार ने जांच का आदेश उन कथित बयानों की व्यापक आलोचना के बाद दिया जिन्हें उकसाने वाला और भड़काऊ बताया गया है।

## छत्तीसगढ़ में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, बारिश से जुड़े हादसों ने बढ़ाई चिंता

**रायपुर।** बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे तक मौसम के प्रतिकूल बने रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस बीच प्रदेश में बारिश से जुड़े हादसों का सिलसिला भी जारी है। दुर्ग जिले में अलग-अलग डूबने की घटनाओं में तीन युवाओं की मौत हो गई।



कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में अब तक मानसून के दौरान हुई कुल बारिश सामान्य से 21 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस पेंड्रारोड में दर्ज किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस भी पेंड्रारोड में दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में मंगलवार को दिनभर बारिश हुई। 24 घंटों के दौरान रायपुर और बिलासपुर संभाग के अनेक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि

## ओडिशा में भारी बारिश, तीन जिलों के लिये 'रेड अलर्ट' जारी

**भुवनेश्वर।** मौसम विभाग ने ओडिशा के तीन जिलों के लिये भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, तटीय इलाके में एक गहरे दबाव का क्षेत्र मंगलवार सुबह उत्तर ओडिशा और उससे सटे पश्चिम बंगाल के ऊपर केंद्रित हो गया।

अगले 24 घंटों के दौरान इस मौसम प्रणाली के उत्तर ओडिशा, दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। बालेश्वर शहर में सबसे अधिक 25 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि नीलगिरि, जलेश्वर और रेमुणा में 24-24 सेमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने सुंदरगढ़, क्योङ्गर और मयूरभंज जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसमें कई स्थानों पर बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।

## आंध्र प्रदेश में ट्रक-वैन की टक्कर से तीन श्रद्धालुओं की मौत, नौ घायल

**विजयानगरम।** आंध्र प्रदेश में विजयानगरम जिले के चेन्नुर गांव के पास मंगलवार को तेज रफ़्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस के अनुसार तीन परिवार के करीब 16 लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में भर्ती कराया गया, जहां लिए ओडिशा के रायगड़ा जा रहे थे। जब उनकी वैन चेन्नुर गांव के पास रुकी, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ़्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में चिंतापल्ली रामबाबू (50), मज्जी



नारायण राव (50) और बी. मोहन नायडू (8) की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। दुर्घटना में घायल हुए नौ लोगों को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार दो लोगों की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात सुचारु कराया।

## सुप्रीम कोर्ट का बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को रिहा करने के निर्देश

**नयी दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह हुए विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए उन सभी छात्रों को मंगलवार को रिहा करने का आदेश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार और असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा केरल सरकारों से जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस कर्मियों को आई चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच ज़रूरी है। न्यायालय ने इस मामले में अंतरिम निर्देशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए यह भी संकेत दिया कि वह अपने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन कर सकती है।



## राज्यसभा में विपक्ष अड़ा, हंगामे के कारण कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

**नयी दिल्ली।** नीट यूजी परीक्षा लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर धरना देने और संसद मार्च निकालने वाले छात्रों तथा अन्य प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब पर अड़े विपक्ष ने लगातार सातवें दिन मंगलवार को भी राज्यसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मानसून सत्र का आज सातवां दिन है और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते अब



तक एक दिन भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो पा सकी है। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की विपक्ष के सदस्यों ने अपनी जगहों से उठकर शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति ने हंगामे के बीच ही शून्यकाल चलाना चाहा लेकिन शोर शराबा बढ़ता देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी।

## सड़क हादसों में तीन की मौत बाइक सवारों को ट्रक ने मारी टक्कर, महिला को विद्युत विभाग की गाड़ी ने कुचला

**बस्तर/मनेन्द्रगढ़/दत्तेवाड़ा।** छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में तीन जिलों में सोमवार-मंगलवार को हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। बस्तर में डंपर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई और मनेन्द्रगढ़ में कार की टक्कर से गिरी महिला को विद्युत विभाग की गाड़ी ने कुचल दिया, तो वहीं दत्तेवाड़ा में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गई।



## टिप्पर की टक्कर से बाइक सवारों की मौत

**जगदलपुर।** बस्तर जिले के जगदलपुर-चित्रकोट मुख्य मार्ग पर सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। बड़ांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छापर

भानपुरी के पास तेज रफ़्तार टिप्पर ने पीछे से एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक सवार अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे टिप्पर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही दम

मेडिकल कॉलेज डिमरापाल, जगदलपुर भिजवाया। मृतकों की पहचान छापर भानपुरी निवासी पीलाराम कश्यप और जीरो राम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही टिप्पर और उसके चालक की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ़्तार और लापरवाही से वाहन चलाना माना जा रहा है।

## केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के पुनर्गठन की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति

**नयी दिल्ली।** केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) के कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सीएससीएस के कैडर पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति समय-समय पर होने वाली कैडर समीक्षा के तहत सेवा संरचना, कार्यभार और प्रशासनिक आवश्यकताओं का आकलन करेगी। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सीएससीएस कैडर की समीक्षा एक नियमित नीतिगत प्रक्रिया है, जिसमें कैडर की वर्तमान संख्या, बदलती प्रशासनिक जरूरतों और कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन पर निर्णय लिया जाता है। सरकार ने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय में कार्यरत मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। रिक्त पद उपलब्ध

होने पर पात्र एमटीएस कर्मचारियों को जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए) के पद पर पदोन्नत किया जाता है, जो केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा केरल सरकारों से जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस कर्मियों को आई चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच ज़रूरी है। न्यायालय ने इस मामले में अंतरिम निर्देशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए यह भी संकेत दिया कि वह अपने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन कर सकती है।



सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है। सरकार के अनुसार नवगठित समिति कैडर समीक्षा के दौरान सेवा संरचना और पदानुक्रम का परीक्षण करेगी तथा भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक सुधारों पर अपनी सिफारिशें देगी। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केंद्रीय सचिवालय की कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ कर्मचारियों के कैरियर विकास को भी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।

**नयी दिल्ली।** इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में मेटा के वैश्विक प्रमुख को तलब किया है। इस बीच मेटा ने वीडियो हटाए जाने पर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई तकनीकी त्रुटि के कारण हुई थी और वीडियो को बहाल कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और मेटा की ओर से दी गयी तकनीकी त्रुटि की सफाई के साथ-साथ उन परिस्थितियों की भी जांच कर रही है, जिनके कारण वीडियो हटाया गया। इसी सिलसिले में मंत्रालय ने



मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) के अधिकारियों को तलब किया है। मेटा के प्रवक्ता ने वीडियो बहाल होने

के बाद मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, यह सामग्री गलती से हटा दी गयी थी और अब उसे बहाल कर दिया गया है। मोदी का यह वीडियो 23 जुलाई को अपलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित छात्र प्रदर्शन के दौरान 'जेन-जेड' को संबोधित करते हुए शिक्षा सुधारों और परीक्षा प्रणाली पर अपनी बात रखी थी। अपने संबोधन में मोदी ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान लाने और फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने पेपर लीक के मामलों

में सख्त सजा और विशेष अदालतों से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार ने लगभग 22 लाख छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित नहीं होने दिया और युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वीडियो बहाल किए जाने से पहले भारत में फेसबुक उपयोगकर्ताओं को एक संदेश दिखाई दे रहा था, जिसमें कहा गया था कि कानूनी अनुरोध के बाद इस वीडियो की क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्धता सीमित कर दी गई है।



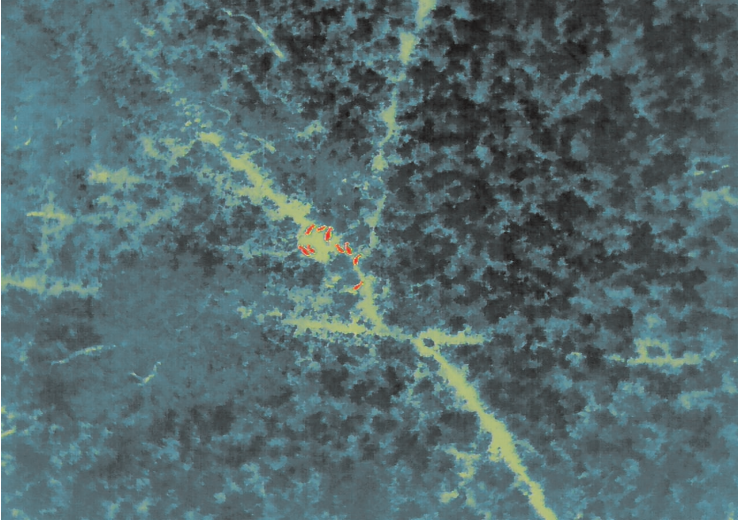


# थर्मल ड्रोन से लैस हुआ बस्तर वन मंडल : अब रात में भी होगी जंगलों की निगरानी

वन्यजीवों की सुरक्षा, अवैध कटाई और शिकार पर लगेगी लगाम, जल्द बस्तर को मिलेगा अपना थर्मल ड्रोन

## जगदलपुर/मूक पत्रिका

**पवन कुमार नाग** – बस्तर के घने जंगलों की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बस्तर वन मंडल अब आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है। वन विभाग द्वारा कांकेर वन मंडल के सहयोग से थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरे के माध्यम से जंगलों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष रूप से रात्रिकालीन निगरानी की जा रही है। इस तकनीक से वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ-साथ अवैध कटाई, लकड़ी तस्करी और शिकार जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिल रही है।थर्मल इमेजिंग तकनीक शरीर की ऊष्मा हीट सिग्नेचर को पहचानने में सक्षम है। इसके माध्यम से घने जंगलों और रात के अंधेरे में भी वन्यजीवों एवं मानव गतिविधियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इससे वन विभाग को भालू, तेंदुआ, हाथी सहित अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल रही



है।वन विभाग इस तकनीक का उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी कर रहा है। वन क्षेत्र से लगे ग्रामीण इलाकों में यदि हाथियों अथवा अन्य जंगली जानवरों की

गतिविधि की सूचना मिलती है, तो थर्मल ड्रोन के जरिए तत्काल निगरानी कर उनकी लोकेशन का पता लगाया जाता है। इसके आधार पर ग्रामीणों को समय रहते सतर्क किया जाता है,

जिससे जन-धन की हानि की संभावना कम होती है। इसके अलावा जंगलों में अवैध कटाई, लकड़ी तस्करी और वन्यजीवों के शिकार जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर भी थर्मल ड्रोन प्रभावी साबित हो रहा है। रात के समय भी सदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर ड्रोन से प्राप्त फुटेज के आधार पर वन विभाग की क्रिक रिस्पांस टीम (क्लस्त्र) तत्काल कार्रवाई कर रही है।डीएफडो बस्तर उत्तम गुप्ता ने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में थर्मल ड्रोन बस्तर वन मंडल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो रहा है। पिछलाहल कांकेर वन मंडल के सहयोग से ड्रोन उपलब्ध कराकर निगरानी की जा रही है तथा जल्द ही बस्तर वन मंडल को भी अपना थर्मल ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से रात्रिकालीन गश्त अधिक प्रभावी हुई है और वनकर्मियों की सुरक्षा भी बेहतर हुई है। बस्तर की समृद्ध जैविक विविधता के संरक्षण के लिए वन विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

## लखौली स्कूल में 7 लाख से बनेगा आधुनिक बालिका शौचालय

**आरंग।** शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखौली में अध्ययनरत छात्राओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ‘त ऋतु त’ योजना के तहत स्वीकृत 7 लाख रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक बालिका शौचालय का सोमवार को वैदिक विधि-विधान और पूजा-अर्चना के साथ भूमिपूजन संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत राज्य गीत एवं स्वागत गीत से हुई, जिसने समारोह में सभा बांध दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ग्राम पंचायत सरपंच हिरामन साहू ने कहा कि छात्राओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण



उपलब्ध कराना पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारी है।?उन्होंने बताया कि इस नए परिसर में अत्याधुनिक सैनिटेशन व्यवस्था, बेहतर जल निकासी, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, ईसिनरेटर और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित ठेकेदार व अधिकारियों को निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।?विद्यालय परिवार एवं शिक्षकों ने इस पहल की सराहना

करते हुए कहा कि आधुनिक शौचालय बनने से छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार होगा, जिससे स्कूल में उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ेगी।?समारोह में उपसरपंच श्रीमती भीमा मोहन साहू, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पंचगण, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्राएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आधार प्रदर्शन के बाद प्रसाद वितरण कर आयोजन का समापन किया गया।

## रायगढ़ कलेक्ट्रेट में ACB का बड़ा एक्शन: मुआवजा दिलाने के नाम पर १50 हजार का हस्ताक्षरित चेक लेते बाबू गिरफ्तार, जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ में भी यह कर्मचारी था कार्यरत

**सर्पदंश मुआवजा दिलाने के बदले मांगी रिश्त**

### रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय के राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा में पदस्थ बाबू राजकुमार सदार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एच) बिलासपुर ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने वर्ष 2023 में सर्पदंश से मृत महिला की मुआवजा राशि शीघ्र बैंक खाते में जारी कराने के बदले १50,000 की रिश्त मांगी। शिकायतकर्ता विजय सदार ने इसकी शिकायत एचन्स की थी।

**नकद नहीं, गारंटी के तौर पर मांगा हस्ताक्षरित चेक-**शिकायत के अनुसार आरोपी बाबू ने कहा था



कि मुआवजा राशि मिलने के बाद १50,000 देना होगा और तब तक गारंटी के रूप में १50,000 का हस्ताक्षरित चेक जमा करना होगा।

शिकायत का सत्यापन होने के बाद एच ने जाल बिछाया। 28 जुलाई 2026 को जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को हस्ताक्षरित चेक सौंपा,

टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

### भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई

एच ने आरोपी राजकुमार सदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

अधिकारियों के अनुसार रिश्त की नकद राशि लेने के बजाय गारंटी के रूप में हस्ताक्षरित चेक मांगकर रिश्तखोरी करने और उसी आधार पर गिरफ्तारी का यह एक अनोखा मामला माना जा रहा है।

### बेमेतरा/मूक पत्रिका

ग्राम नेवनारा स्थित माँ चंडी आश्रम में आयोजित तीन दिवसीय आवासीय व्याख्यान एवं संगीत प्रशिक्षण कार्यशाला का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में सफल समापन हुआ। कार्यशाला में जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों प्रशिक्षार्थियों ने संगीत, मानस व्याख्यान, स्वर-साधना, मंच संचालन और रामचरितमानस गायन की बारीकियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।कार्यक्रम में राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संगीतकार उत्तम तिवारी तथा मानस दर्शन के संस्थापक दीपक गुहा सहित कई प्रतिष्ठित संगीत एवं मानस साधकों ने सहभागिता की। दीपक गुहा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को जोड़ने



और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए रामचरितमानस के संवाद और परंपराओं को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।प्रशिक्षण सत्र में त्रेता चंद्राकर, बलराम साहू, विनय ताप्रकार, राजा तंतुवाय, ठेकेलाल देवांगन, राजकुमार ताप्रकार, रोहित गंधर्व, हेमलता साहू, महाराज दीन धीवर, मोतीलाल साहू, टिकेंद्र धीवर, हीरानंद साहू एवं रामा साहू ने प्रशिक्षार्थियों को प्रभावी व्याख्यान शैली, संगीत और मंचीय प्रस्तुति का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।समापन समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी, जगपद सदस्य रेखा पोषण सिन्हा, सरपंच लोकेश साहू, समाजसेवी देवेंद्र जैन, मनोज तिवारी, शालिक राम वर्मा, डॉ. बी.आर. साहू, खिलेश्वरी साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति और रामचरितमानस के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माँ भद्रकाली जिला मानस संघ, बेमेतरा के अध्यक्ष देवलाल सिन्हा ने जिला मुख्यालय में मानस भवन निर्माण की मांग रखते हुए कहा

कि इससे मानस साधकों और सांस्कृतिक गतिविधियों को स्थायी मंच मिलेगा। उन्होंने आयोजन की सफलता में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों, सहयोगियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। आयोजन को सफल बनाने में शालिक राम साहू, माखन साहू, विष्णु साहू, गजेंद्र वर्मा, मदन सिन्हा, कल्याणी सेन, लता निषाद, छान साहू, उत्तम साहू, महेश साहू, नरेंद्र जायसवाल, डॉ. ओंकार चंद्राकर, ईश्वर सिंह राजपूत, महेंद्र चौहान, धर्मेन्द्र साहू, रामायण यदु, राजकुमार निषाद, संजय साहू, लोकेंद्र सेन, संतोष साहू, ओम यदु, अजय यदु, डॉ. ललित साहू, श्रीमती ममता साहू, उदयराम वर्मा एवं रामायतार साहू सहित अनेक कार्यकर्ताओं का उल्लेखनीय योगदान रहा।

## मोल्ड-टेक पैकेजिंग लिमिटेड का Q1 मुनाफ़ा 14.17% बढ़ा

हैदराबाद की रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी ने 30 जून को खत्म हुई तिमाही में 25.57 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि एक साल पहले यह 22.40 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू सालाना आधार पर 24.90 प्रतिशत बढ़कर 240.56 करोड़ रुपये से 300.45 करोड़ रुपये हो गया। एबिटडा 19.10 प्रतिशत बढ़कर 56.43 करोड़ रुपये हो गया, जबकि प्रति किलोग्राम एबिटडा क्यू1 एफवाय27 में 46.68 रुपये के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर (हिस्टोरिकल हाई) पर पहुंच गया; इसकी तुलना में क्यू1 एफवाय26 में यह 41.64 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसमें बेहतर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हैदराबाद यूनिट्स के कंसोलिडेशन और ज्यादा मार्जिन वाले फर्मा पैकेजिंग बिज़नेस से बेहतर योगदान का अहम रोल रहा। टेक्स से पहले का प्रॉफिट 13.86 प्रतिशत बढ़कर 34.17 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 30.01 करोड़ रुपये था। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जे. लक्ष्मण राव ने कहा:

युद्ध जैसी मौजूदा स्थिति के बावजूद, मोल्ड-टेक पैकेजिंग लिमिटेड ने एप्रैलाय 2026-27 की मजबूत शुरुआत की और 30 जून, 2026 को खत्म हुई पहली तिमाही में शानदार परफॉर्मेंस दी। हैदराबाद में यूनिट्स को एक साथ लाने और ज्यादा कैपेसिटी का इस्तेमाल करने से बेहतर एबिटडा हासिल हुआ इस तिमाही के दौरान भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बढ़ने के बावजूद, कंपनी के कामकाज, सप्लाई चेन या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि इनपुट की बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर प्रभावी ढंग से डाल दिया गया। यह शानदार ऑल-राउंड परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल एक्ससेलेंस पर मोल्ड-टेक के पक्के फेकस और हैदराबाद में यूनिट्स को रणनीतिक रूप से एक साथ लाने के नतीजों को दिखाता है, जिससे अब मुनाफ़ा बढ़ रहा है। कंपनी को भरोसा है कि आने वाली तिमाहियों में भी यह सकारात्मक तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि मुख्य सेगमेंट (जैसे फर्मा, फूड और एफएमसीजी) में अच्छी डिमांड है और ऑपरेशनल क्षमता

को बेहतर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।उन्होंने कहा, एप्रैलाय 27 की पहली तिमाही में प्रति किलोग्राम एबिटडा रू 46.68 के 'अब तक के सबसे ऊंचे स्तर' (हिस्टोरिकल हाई) पर पहुंच गया, जबकि एप्रैलाय26 की पहली तिमाही में यह रू 41.64 प्रति किलोग्राम था। इसकी वजह बेहतर क्षमता का इस्तेमाल, हैदराबाद यूनिट्स का एकीकरण और ज्यादा मार्जिन वाले फर्मा पैकेजिंग बिज़नेस से मिला बेहतर योगदान था। फर्मा पैकेजिंग प्लांस पर बात करते हुए, मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फर्मा बिज़नेस डिवीजन के इंचार्ज जे. राणा प्रताप ने कहा, डायनोस्टिक्स समेत फर्मा पैकेजिंग में बहुत बड़ा मौका है और हमारी योजना डोज़ेज पेन जैसे ज्यादा मुनाफ़े वाले क्षेत्रों में उतरने की है। हम मोल्ड मेकिंग और रोबोटिक्स में अपनी गहरी जानकारी का इस्तेमाल करके जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के क्षेत्र में उतरने के तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं।

## दुर्ग, बालोद और बेमेतरा के तुलनात्मक अध्ययन में जुलाई माह में बिजली खपत में 53 से 56 प्रतिशत तक की कमी दर्ज

स्मार्ट मीटर से नहीं बढ़ती बिजली खपत, अध्ययन में सामने आए तथ्य



मीटर के कारण नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपकरणों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है।दुर्ग शहर में 400 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले 240 चयनित स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के अध्ययन में जुलाई माह में कुल बिजली खपत 76,257 यूनिट दर्ज की गई, जबकि जून में यह 1,65,411 यूनिट और मई में 1,75,451 यूनिट थी। इस प्रकार जुलाई में लगभग 53 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। इसी प्रकार बालोद



शहर के 241 चयनित स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं में जुलाई माह की कुल खपत 74,847 यूनिट रही, जबकि जून में 1,62,127 यूनिट और मई में 1,54,110 यूनिट दर्ज की गई। यहां भी जुलाई में लगभग 54 प्रतिशत की कमी देखने को मिली।बेमेतरा डिवीजन के बेमेतरा टाउन क्षेत्र में 400 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले 241 चयनित उपभोक्ताओं के विश्लेषण में मई माह की खपत 1,59,812 यूनिट, जून में

1,79,401 यूनिट तथा जुलाई में घटकर 78,902 यूनिट दर्ज की गई। इस प्रकार जुलाई माह में लगभग 56 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई।अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि जिन उपभोक्ताओं के यहां अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, उनकी बिजली खपत में भी मई और जून माह में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि तथा जुलाई माह में कमी दर्ज हुई है। इससे स्पष्ट है कि अधिक बिजली खपत का कारण स्मार्ट मीटर नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर एवं अन्य विद्युत उपकरणों का अधिक उपयोग है।कंपनी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 400 यूनिट से अधिक रहती है, उन्हें मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान

योजना का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे उनके बिजली बिल अधिक दिखाई देते हैं। हालांकि जुलाई माह में खपत कम होने से अगस्त में जारी होने वाले बिजली बिलों में राहत मिलने की संभावना है तथा अधिक उपभोक्ता योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सीएसपीडीसीएल ने यह भी जानकारी दी कि स्वीकृत भार से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब सप्लाई अप्रॉडिंग शुल्क की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब लगातार तीन माह तक उच्चतम मांग अधिक दर्ज होने पर यह राशि वर्ष में केवल एक बार दिसंबर माह के बिल (जो जनवरी में जारी होगा) में जोड़ी जाएगी।

## नेवनारा में तीन दिवसीय व्याख्यान एवं संगीत प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल समापन, सैकड़ों प्रशिक्षार्थियों ने लिया प्रशिक्षण



कल्पना योगेश तिवारी, जगपद सदस्य रेखा पोषण सिन्हा, सरपंच लोकेश साहू, समाजसेवी देवेंद्र जैन, मनोज तिवारी, शालिक राम वर्मा, डॉ. बी.आर. साहू, खिलेश्वरी साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति और रामचरितमानस के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माँ भद्रकाली जिला मानस संघ, बेमेतरा के अध्यक्ष देवलाल सिन्हा ने जिला मुख्यालय में मानस भवन निर्माण की मांग रखते हुए कहा

कि इससे मानस साधकों और सांस्कृतिक गतिविधियों को स्थायी मंच मिलेगा। उन्होंने आयोजन की सफलता में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों, सहयोगियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। आयोजन को सफल बनाने में शालिक राम साहू, माखन साहू, विष्णु साहू, गजेंद्र वर्मा, मदन सिन्हा, कल्याणी सेन, लता निषाद, छान साहू, उत्तम साहू, महेश साहू, नरेंद्र जायसवाल, डॉ. ओंकार चंद्राकर, ईश्वर सिंह राजपूत, महेंद्र चौहान, धर्मेन्द्र साहू, रामायण यदु, राजकुमार निषाद, संजय साहू, लोकेंद्र सेन, संतोष साहू, ओम यदु, अजय यदु, डॉ. ललित साहू, श्रीमती ममता साहू, उदयराम वर्मा एवं रामायतार साहू सहित अनेक कार्यकर्ताओं का उल्लेखनीय योगदान रहा।

**आलोक सिटी मॉल, संजय मार्केट और शांति लॉज गली में चला विशेष अभियान, नागरिकों एवं व्यापारियों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करने की अपील**

## नालों से निकला 7 ट्रेक्टर-ट्रॉली प्लास्टिक कचरा, आयुक्त ने खुद खड़े रहकर कराई सफाई

### रायगढ़/मूक पत्रिका

शहर को जलभराव से मुक्त बनाने के लिए निगम प्रशासन द्वारा लगातार नाला-नालियों की सफाई एवं सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय ने आलोक सिटी मॉल के सामने, संजय मार्केट, सुभाष चौक मार्ग एवं शांति लॉज गली का निरीक्षण कर स्वयं मौके पर खड़े रहकर सफाई एवं जल निकासी संबंधी कार्य कराए।निरीक्षण के दौरान आलोक सिटी मॉल के सामने स्थित नाला चैंबर पूरी तरह जाम मिला। सफाई शुरू होने पर नाला चैंबर से लगभग सात ट्रेक्टर-ट्रॉली पानी की प्लास्टिक बोतलें, डिस्पोजल सामग्री, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक की शीशियां, पैकेजिंग सामग्री तथा अन्य ठोस कचरा एवं मलबा निकला। बड़ी मात्रा में जमा इस कचरे के कारण नाला पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था, जिससे बरसात का पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इससे बरसात के दौरान संजय मार्केट और सुभाष चौक मार्ग पर जलभराव का प्रमुख कारण बन रही थी।आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय ने तत्काल नाला चैंबर की पूरी सफाई कराकर जल



निकासी को सुचारु कराया। इसके बाद उन्होंने शांति लॉज गली का निरीक्षण किया, जहां पाया गया कि छोटी नाली का पानी बड़े नाले तक नहीं पहुंच रहा था। समस्या के स्थायी समाधान के लिए

सड़क को काटकर छोटी नाली को बड़े नाले से जोड़ा गया तथा पूरी नाली की सफाई कराकर जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। इससे क्षेत्र में वर्षा के दौरान पानी का तेजी से निकास हो

सकेगा और जलभराव की समस्या में कमी आएगी।निरीक्षण के दौरान आयुक्त श्री क्षत्रिय ने कहा कि नगर निगम नियमित रूप से नाला-नालियों की सफाई करता है, लेकिन नागरिकों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्लास्टिक बोतलें, डिस्पोजल, सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्माकोल, पैकेजिंग सामग्री तथा अन्य ठोस कचरा नालों में फेंकने के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यही कचरा नालों में जमा होकर जल निकासी को बाधित करता है और थोड़ी सी बारिश में भी जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक और व्यापारी की जिम्मेदारी है। यदि कचरे का उचित पृथक्करण कर उसे डस्टबिन या नगर निगम की डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को सौंपा जाए, तो नाला-नालियों के जाम होने की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। आयुक्त श्री क्षत्रिय ने शहरवासियों एवं व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि नाला-नालियों में किसी भी प्रकार का कचरा, प्लास्टिक, डिस्पोजल या निर्माण मलबा न डालें। स्वच्छता बनाए रखना केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि शहर में निवासरत प्रत्येक नागरिक की साझा

जिम्मेदारी है। जनसहभागिता और जागरूकता से ही शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं जलभराव मुक्त बनाया जा सकता है।निगम प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नाला-नालियों में कचरा फेंकते हुए दिखाई दे तो उसे समझादेश दे तथा स्वच्छता अभियान में सहभागी बनें। नगर निगम आने वाले दिनों में भी ऐसे स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाकर जल निकासी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा।

### नाला-नालियों में कचरा फेंकना पड़ सकता है महंगा

निगम प्रशासन ने नागरिकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करें। नाला-नालियों में प्लास्टिक, डिस्पोजल, निर्माण मलबा अथवा अन्य ठोस कचरा फेंकना न केवल जलभराव का कारण बनता है, बल्कि यह नियमों का उल्लंघन भी है। ऐसे मामलों में निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। स्वच्छ एवं जलभराव मुक्त रायगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी

आवश्यक है।

### सिविक सेंस में पिछड़ा रायगढ़ नगर निगम

निगम प्रशासन का कहना है कि रायगढ़ तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन शहर में नाला-नालियों में प्लास्टिक, डिस्पोजल, बोतलें और अन्य कचरा फेंकने की प्रवृत्ति आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। यही लापरवाही बरसात के दौरान जलभराव, गंदगी और यातायात बाधित होने जैसी समस्याओं को जन्म देती है। किसी भी शहर की पहचान केवल सड़कों, भवनों और विकास कार्यों से नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले नागरिकों के सिविक सेंस से होती है। जब तक प्रत्येक नागरिक और व्यवसायी सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर उसकी सुरक्षा और स्वच्छता की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक रायगढ़ को एक स्वच्छ, व्यवस्थित और विकसित शहर बनाने का लक्ष्य अधूरा रहेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी लोगों को काल कर सड़स संबंध में फेडबैक ली जाती है, जिस पर रायगढ़ का अंक बहुत कम रहता है।























